RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 056
दि. 28.11.2025,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

गिरते साम्राज्य की गूंज, 21 साल की सजा ने शेख हसीना की राजनीति को फिर हिला दिया

(जीएनएस)। ढाका की दोपहर हमेशा की तरह भीड़भाड़ और गर्म हवा से भरी थी, लेकिन बुधवार का दिन कुछ अलग था—सड़कों पर चर्चा थी, टीवी चैनलों पर बहस, और राजनीतिक गलियारों में अजीब-सी खामोशी। कारण था वह फैसला जिसे बांग्लादेश की राजनीति में वर्षों तक याद किया जाएगा। देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को राजधानी की एक विशेष अदालत ने जमीन आवंटन से जुड़े तीन मामलों में कुल 21 साल की कैद की सजा सुनाई। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि उस राजनीतिक अध्याय का अगला पृष्ठ था, जिसमें कभी शक्तिशाली रही एक नेता धीरे-धीरे अपने ही बनाए साम्राज्य से दूर होती जा रही थी।

राजुक न्यू टाउन प्रोजेक्ट का नाम बांग्लादेश में नया नहीं है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भूमि का नहीं था, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग की उस छाया का था जो वर्षों से दबे शब्दों में चर्चा में रही। अदालत ने बताया कि 30 कट्ठा सरकारी भूमि, जो आम नागरिकों के लिए नियोजित थी, उसे अवैध रूप से हसीना को आवंटित किया गया। विशेष अदालत-5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने तीनों मामलों में सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। अदालत में वह जानी-पहचानी खामोशी थी, जो तब उतरती है जब फैसला बहुत भारी हो, और आरोपी उपस्थित न हों। हसीना, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा

वाजेद पुतुल—तीनों गैरहाजिर थे, जैसे किसी अनदेखे अध्याय की शुरुआत होने वाली हो। अदालत का स्वर साफ था—आरोप सिर्फ हसीना पर नहीं, उनके परिवार पर भी था। बेटे सजीब वाजेद जॉय को पांच साल की कैद और एक लाख टका जुर्माना, बेटी साइमा वाजेद पुतुल को पांच साल की सजा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह आवंटन न सिर्फ अवैध था, बल्कि इसके पीछे सत्ता का वह दुरुपयोग था, जिसने वर्षों तक बांग्लादेश की राजनीति को प्रभावित किया। बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने जनवरी में कुल छह मामले दर्ज किए थे, जिनमें तीन का फैसला आज आया, जबकि बाकी तीन 1 दिसंबर को तय किए जाएंगे। यह सिर्फ शुरुआत थी—क्योंकि इन फैसलों की गूंज अभी बहुत दूर तक जाने वाली थी।

राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब शेख हसीना पर क़ानूनी प्रहार हुआ हो। कुछ ही दिन पहले—17 नवंबर को—देश के आपराधिक न्यायाधिकरण ने एक अलग मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। वह फैसला अतिशय गंभीर था, और उसके बाद से हसीना और उनका परिवार सभी अदालतों से अनुपस्थित है। किसी को नहीं पता वह कहां हैं, लेकिन यह तय है कि अदालत का शिकंजा हर सुनवाई के साथ और कसता जा रहा है। हसीना, जो कभी बांग्लादेश की सत्ता का सबसे मजबूत चेहरा थीं, अब कानूनी संकटों के बीच एक अंधेरी राह पर चलते दिख रही हैं। ढाका के गलियारों में चर्चा थी कि यह मुकदमे सिर्फ जमीन आवंटन से जुड़े नहीं, बल्कि उस सत्ता-प्रणाली की परतें खोल रहे हैं जहाँ निर्णय अक्सर शक्ति के तराजू पर तौले जाते थे। अदालत ने कहा कि हसीना द्वारा प्राप्त भूखंड के लिए न कोई दस्तावेज़ जमा किया गया था, न कोई औपचारिक आवेदन। यह एक सीधा उदाहरण था कि कैसे सत्ता की ऊँचाई कभी-कभी कानून की नींव को नजरअंदाज कर देती है।

अंतरराष्ट्रीय हलकों में भी आज के फैसले को लेकर उत्सुकता और चिंता दोनों थी। एक लंबे समय तक दक्षिण एशिया में मजबूत राजनीतिक प्रभाव रखने वाली नेता अब लगातार कोर्ट के घेरे में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश का राजनीतिक परिदृश्य आने वाले महीनों में पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि यह मुकदमे केवल एक नेता को नहीं, बल्कि एक युग को चुनौती दे रहे हैं। ढाका की अदालत का यह फैसला आने वाले वर्षों की राजनीति का रुख तय कर सकता है। शेख हसीना के खिलाफ छह मामलों की लंबी सूची है—हर मामला एक अलग पन्ना, लेकिन कहानी एक ही है—वह कहानी जिसमें कभी सत्ता की ऊँचाई पर खड़ी नेता आज कानून की गहराइयों में उतरती जा रही है। और इन घटनाओं के पीछे वह सियासी हलचल है, जिसकी कंपकंपी सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, पूरे क्षेत्र की कूटनीति में महसूस की जा रही है। आज का दिन बांग्लादेश के इतिहास में इसलिए भी दर्ज होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि सत्ता, न्याय और लोकतंत्र के उस संघर्ष की गवाही है, जो हर देश अपनी राजनीति के किसी न किसी दौर में देखता है। शेख हसीना का साम्राज्य ढह रहा है—धीरे, लेकिन लगातार—और उसकी गूंज आने वाले समय में और दूर तक सुनाई देगी।

अंतरिक्ष का द्वार अब युवा हाथों में, स्काईरूट के इन्फिनिटी कैंपस ने भारत की नई उड़ान को दिया आकाश

(जीएनएस)। नई दिल्ली की शाम सामान्य दिनों की तरह थी, मगर गुरुवार का दिन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक नई शुरुआत लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्काईरूट एयरोस्पेस के अत्याधुनिक 'इन्फिनिटी कैंपस' का उद्घाटन कर रहे थे, तो उनके शब्दों में वही उत्साह था जो किसी देश के भविष्य को नई दिशा देता है। उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं, बल्कि भारत की युवा पीढ़ी—जेन Z—के लिए अंतरिक्ष के सबसे बड़े दरवाज़े खोलने जैसा क्षण है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जो बदलाव पिछले कुछ वर्षों में आए हैं, वे भारत को उस नई ऊँचाई पर ले जा रहे हैं जहाँ नवाचार, साहस और युवा ऊर्जा एक साथ उड़ान भरते हैं।

प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि जब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला था, तब कई लोगों को उम्मीद थी कि इससे भारत की प्रतिभा को अवसर मिलेगा, लेकिन आज परिणाम उम्मीद से कहीं अधिक बड़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में खड़ा हो चुका है जिनके पास दुनिया की सबसे उन्नत लॉन्च साइट्स, मजबूत इंजीनियरिंग क्षमताएँ और अत्याधुनिक विनिर्माण प्रणालियाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह नया वातावरण इतना खुला है कि युवा उद्यमी जोखिम लेने से नहीं डरते, बल्कि नई सीमाएँ खींच रहे हैं और उन जगहों पर कदम रख रहे हैं जहाँ पहले केवल सरकारी संस्थाएँ ही पहुँच पाती थीं।

इन्फिनिटी कैंपस की कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। करीब 20,000 वर्ग फुट में फैला यह विशाल केंद्र किसी आधुनिक विज्ञान कथा फिल्म की तरह दिखता है। यहाँ उस तरह की तकनीक, मशीनें और रचनात्मक माहौल मौजूद है, जहाँ एक विचार कुछ ही महीनों में एक वास्तविक रॉकेट का स्वरूप ले सकता है। यह केंद्र हर महीने एक कक्षीय रॉकेट तैयार करने की क्षमता रखता है—एक ऐसी उपलब्धि जिसे कभी दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियाँ ही हासिल कर पाती थीं। इसी कैंपस में प्रधानमंत्री ने स्काईरूट के पहले आर्बिटल रॉकेट—विक्रम-1—का अनावरण किया, जो आने वाले वर्षों में सैकड़ों उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की परिपक्वता का पहला गंभीर कदम है।

विक्रम-1 के अनावरण के साथ ही देशभर में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और छात्रों में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। ऐसा क्यों न हो—दुनिया में छोटे उपग्रहों की मांग लगातार बढ़ रही है। संचार, मौसम, रक्षा, कृषि, शिक्षा, इंटरनेट—हर क्षेत्र में छोटे और हल्के उपग्रहों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था केवल दोगुनी नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ने वाली है और इसके केंद्र में भारतीय युवाओं की प्रतिभा, शोध क्षमता और तकनीकी कौशल होगा। यह वही क्षण है जब भारत का युवा—जो कभी केवल बड़े सपने देखा करता था—अब उन्हें अपनी ही धरती पर पूरा होते देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदीनं कहा कि इसरो ने दशकों तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को अपने कंधों पर उठाया और उसे उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ आज पूरी दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और मजबूत तकनीकी साझेदार मानती है। उन्होंने कहा कि इसरो की विरासत अब हाथों से फिसल नहीं रही, बल्कि और विस्तृत होकर निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और युवा वैज्ञानिकों के कंधों पर फैल रही है। यह साझेदारी ही भारत को अंतरिक्ष दौड़ में नए युग का नेतृत्व करने की क्षमता दे रही है। इसरो की विरासत, निजी स्टार्टअप्स की ऊर्जा और सरकार की खुली नीतियों का यह संगम आज भारत को उस रास्ते पर ले आया है जिसकी कल्पना सिर्फ बड़ी शक्तियाँ ही करती थीं। अब अंतरिक्ष सिर्फ आसमान में चमकते सितारों की दुनिया नहीं—यह भारत के युवाओं के करियर, रोजगार, नवाचार और सपनों की नई मंज़िल बन चुका है। 'इन्फिनिटी कैंपस' का उद्घाटन सिर्फ एक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं, बल्कि उस यात्रा की शुरुआत है जहाँ भारत की अगली पीढ़ी पृथ्वी से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से अपना भविष्य लिखेगी। आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है, क्योंकि यह भविष्य का वह उद्घाटन है जिसमें आकाश सीमा नहीं, बल्कि पहला पड़ाव है।

मियामी शिखर से पहले भूचाल, ट्रंप के फैसले ने वैश्विक कूटनीति में मचा दी हलचल

(जीएनएस)। वाशिंगटन की ठंडी दोपहर में जब दुनिया की निगाहें जी-20 सम्मेलन के अंतिम चरण पर टिकी थीं, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कदम उठा लिया, जिसने वैश्विक कूटनीति की जमीन हिला दी। घोषणा बिल्कुल अचानक, लेकिन अंदाज़ बेहद दृढ़। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगले वर्ष फ्लोरिडा के मियामी में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका को आमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका की ओर से दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली सभी सब्सिडी और सरकारी भुगतान भी तत्काल रोक दिए गए। यह मानो दो देशों के बीच बढ़ रहे तनाव पर राष्ट्रपति ने एक आखिरी, लेकिन सबसे भारी मुहर लगा दी हो।

ट्रंप ने अपने बयान में आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका ने इस बार के जी-20 सम्मेलन की समाप्ति पर मेजबानी हस्तांतरण की प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित किया, जिससे अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ प्रतिनिधि को सम्मानपूर्वक प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी गई। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे देश की सदस्यता या उपस्थिति किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन के लिए उचित नहीं हो सकती, जहाँ बुनियादी कूटनीतिक शिष्टाचार का पालन ही न किया जाए। उनका यह बयान प्रकाश की गति से पूरे विश्व में फैल गया और अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के बीच यह सवाल गूंजने लगा कि क्या यह मात्र कूटनीतिक नाराजगी है या अमेरिका अपने भू-राजनीतिक वर्चस्व को पुनः रेखांकित करने में जुटा है।

पिछले कुछ समय से ट्रंप का दक्षिण अफ्रीका के प्रति अविश्वास खुलकर सामने आ रहा था। वह विशेष तौर पर देश में श्वेत किसानों के कथित उत्पीड़न को लेकर दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को कई बार वैश्विक मंचों पर भी उठाया था। इसी विवाद की पृष्ठभूमि में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में आयोजित जी-20 सम्मेलन का बहिष्कार कर दुनिया को एक संकेत दे दिया था कि दोनों देशों के बीच खाई अब सामान्य नहीं रही। यह खाई अब एक राजनीतिक दरार बन चुकी थी, जिसकी प्रतिध्वनि कूटनीति के लंबे गलियारों में सुनी जा सकती थी।

ट्रंप की प्रतिक्रिया केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि अमेरिकी नीति की दिशा बदलने का ऐलान थी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखकर कहा कि दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी-20 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पिछले सम्मेलन के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधि के प्रति दक्षिण अफ्रीका का व्यवहार "असम्मानजनक और अवमाननापूर्ण" था। यह शब्द पूरी दुनिया के लिए संकेत था कि अमेरिका अब अपने सहयोगियों से अधिक कठोर शर्तों और अधिक सम्मानपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कर रहा है, और इस अपेक्षा के खिलाफ जाने वालों के लिए जगह कम होती जाएगी।

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी आरोपों को दो टूक शब्दों में खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि श्वेत किसानों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा "निराधार, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित" है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार का कहना है कि उनके यहाँ किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव की कोई नीति नहीं है, और अमेरिका की चिंताएँ वास्तविकता से काफी दूर हैं। दोनों देशों के सुर जितने अलग थे, उतना ही गहरा उनका विवाद भी बनता जा रहा था।

विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका का यह कदम केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती हुई शक्ति को भी चुनौती देता है। जी-20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, और किसी सदस्य देश को आमंत्रण सूची से बाहर करना अत्यंत असामान्य कदम माना जाता है।

देशभर में ईडी का बड़ा एक्शन: मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी में रिश्वतखोरी के आरोपों पर दस राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली की सुबह गुरुवार को उस समय अचानक गंभीर हो उठी जब प्रवर्तन निदेशालय की टीमें एक साथ दस राज्यों में निकल पड़ीं और मेडिकल कॉलेजों को शैक्षणिक अनुमोदन दिलाने के बदले कथित रिश्वतखोरी के विशाल नेटवर्क की परतें खोलने के लिए पंद्रह ठिकानों पर धावा बोल दिया। यह कार्रवाई सिर्फ छापेमारी भर नहीं थी, बल्कि मेडिकल शिक्षा की बुनियाद को हिला देने वाले एक ऐसे भ्रष्टाचार मॉडल की खोज थी जिसमें बताया जाता है कि मंजूरी देने वाली संस्था, बिचौलियों और कुछ सरकारी अधिकारियों ने मिलकर मेडिकल कॉलेजों से भारी रकम वसूली और नियमों को ताक पर रखकर उन्हें कोर्स चलाने की अनुमति दी। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश—इन दस राज्यों में एक निर्दिष्ट समय पर ईडी की टीमों ने दस्तक दी और पूरी कार्रवाई को इस तरह अंजाम दिया कि कहीं भी किसी को पहले से भनक नहीं लगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी 30 जून 2025 को दर्ज की गई उस एफआईआर की कड़ी है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत साफ कहा गया था कि मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के लिए बड़े पैमाने पर अवैध धन का लेन-देन हुआ। ईडी को इस बात की भनक भी मिली थी कि यह नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है और इसमें कई स्तरों पर भूमिका निभाने वाले लोग शामिल हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने विभिन्न ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक डाटा, हार्ड डिस्क, मोबाइल रिकॉर्ड, वित्तीय दस्तावेज, बैंक लेन-देन के ब्योरे और कई संवेदनशील दस्तावेजों की तलाश की। यह भी बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर ईडी अधिकारियों को ऐसे कागज़ मिले हैं जिनसे यह साबित हो सकता है कि मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने के बदले एक निश्चित रकम तय थी, और यह रकम कई हाथों से गुजरकर अंततः उन लोगों तक पहुंचती थी जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर कॉलेजों को हरी झंडी दिलाते थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अवैध रूप से अर्जित धन को वैध बनाने की प्रक्रियाएँ भी शामिल थीं, जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और मजबूत हो गया है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि यह कार्रवाई पहली कड़ी मात्र है और आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े लोगों के घरों और दफ्तरों पर फिर से दस्तक दी जा सकती है। कई लोगों को पूछताछ के लिए समन भेजने की तैयारी भी चल रही है और यदि जरूरत पड़ी तो ईडी बड़ी जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई भी कर सकती है। देश में मेडिकल शिक्षा पहले ही सीटों की कमी, बढ़ती फीस और कोर्स अनुमोदन की जटिल प्रक्रियाओं को लेकर विवादों के घेरे में रही है। ऐसे में इस छापेमारी ने एक बार फिर यह सवाल उठा दिया है कि क्या स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में काम करने वाले संस्थानों के भीतर पारदर्शिता की जगह दलाल तंत्र ने ले ली है। ईडी की यह कार्रवाई राजनीतिक स्तर पर भी हलचल मचाने वाली है, क्योंकि यदि इस पूरे नेटवर्क के तार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और सरकारी मशीनरी तक जाते हैं, तो आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बहस और तेज होने की संभावना है।

नौ बार के विधायक सेंगोट्टैयन ने छोड़ा एआईएडीएमके, विजय की टीवीके को मिला अनुभवी चेहरा

(जीएनएस)। चेन्नई की राजनीतिक हवा गुरुवार को अचानक बदलती दिखाई दी जब तमिलनाडु के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, नौ बार के विधायक और पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा तक जनता में गहरी पैठ रखने वाले के.ए. सेंगोट्टैयन ने एआईएडीएमके को अलविदा कहकर तमिल सुपरस्टार विजय की नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कझगम में शामिल होने का फैसला कर लिया। यह घटना महज पार्टी बदलने भर की नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के मौजूदा समीकरणों में एक बड़ा भूचाल मचा देने वाली थी, क्योंकि सेंगोट्टैयन केवल एक नेता नहीं, बल्कि उन चुनिंदा नामों में से हैं जिनके राजनीतिक सफर ने पिछले पाँच दशकों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और जिनकी पकड़ आज भी इरोड और आसपास के जिलों में बेहद मजबूत मानी जाती है। एआईएडीएमके से निष्कासन के एक दिन बाद ही विधानसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने संकेत दे दिया था कि अब उनके राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, और जब गुरुवार को वे टीवीके कार्यालय पहुंचे तो वहाँ उनका स्वागत किसी पुराने योद्धा की तरह किया गया। विजय खुद गुलदस्ता और सदस्यता कार्ड लेकर आगे आए और बड़ी गर्मजोशी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उनके साथ एआईएडीएमके की पूर्व सांसद सत्यभामा भी मौजूद थीं, जिन्हें विजय ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, और इस दृश्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि टीवीके अब सिर्फ एक नवोदित संगठन नहीं, बल्कि तमिलनाडु की बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बनने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है।

विजय ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सेंगोट्टैयन के राजनीतिक सफर को अद्वितीय बताया और कहा कि पिछले पचास वर्षों में जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता और विश्वास टीवीके को ऐसी ताकत देगा जिसकी जरूरत किसी भी उभरती हुई पार्टी को होती है। उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा कि कभी एम.जी.आर. ने मात्र बीस वर्ष की आयु में सेंगोट्टैयन को राजनीति में जगह दी थी, और आज तमिल राजनीति का एक नया अध्याय उसी विश्वास की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि टीवीके के संगठनात्मक ढांचे में सेंगोट्टैयन को बहुत बड़ी भूमिका मिल सकती है, जिससे पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मजबूत जमीन तैयार कर सकेगी। दूसरी तरफ एआईएडीएमके में इस घटनाक्रम को लेकर सन्नाटा है। महासचिव ई.के. पलानीस्वामी ने अक्टूबर में सेंगोट्टैयन को पार्टी-विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित किया था, जिसके बाद सेंगोट्टैयन ने पलानीस्वामी पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए मामले को अदालत तक ले जाने की बात कही थी। जब आज पत्रकारों ने इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर पलानीस्वामी से प्रतिक्रिया चाही, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। इस चुप्पी ने राजनीतिक विश्लेषकों को और अधिक दृढ़ कर दिया कि एआईएडीएमके के भीतर खदबदाहट आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इरोड जिले में जनाधार की बात करें तो सेंगोट्टैयन का नाम पहला माना जाता है। लगातार नौ बार चुनाव जीतने की उपलब्धि बहुत कम नेताओं के पास होती है और यही कारण है कि उनका टीवीके में शामिल होना आने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनके टीवीके के साथ आने से इरोड, कोयंबटूर और पश्चिमी तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, नए गठजोड़ उभरेंगे और यह बदलाव राज्य की राजनीति को एक नई दिशा भी दे सकता है।

संपादकीय

महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई देगी कामयाबी

रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वो इतिहास रचा, जिसका दो दशक से इंतजार था। एक दिवसीय क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने उस कमी को पूरा किया, जो साल 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचकर भी हासिल न हो सकी थी। ऐसे वक्त में जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम को खिताबी दौड़ में कमजोर माना जा रहा था, उसने सात बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया टीम को सेमीफाइनल के एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया था। मुकाबले में मुंबई की जेमिमा रॉड्रिग्स ने 127 रन की तूफानी यादगार पारी खेली। लगता था शुरुआत में कई मैच हारने वाली भारतीय महिला टीम ने अपनी ऊर्जा फाइनल मुकाबले के लिये बचा रखी थी, जिसमें उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रन से हरा दिया। रविवार की रात हरमनप्रीत कौर की कप्तानी ने पासा ही पलट दिया। फिर उनकी टीम ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चालीस हजार से ज्यादा दर्शकों के बीच जीत का जश्न जमकर मनाया। इस जुनूनी जश्न की वे हकदार भी थीं। साथ ही देश के एक अरब चालीस करोड़ लोगों को भी जीत के जश्न में डुबो दिया। लोग इस साल होने वाले कई दुखांत घटनाक्रमों को भुला इस जीत की लय में झूम उठे। यह सुखद आश्चर्य ही था कि टीम ने लगातार तीन हार झेलने के बाद टूर्नामेंट में दमदार वापसी की। सेमीफाइनल में लोग सात बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को कमतर आंक रहे थे। सुखद आश्चर्य देखिये कि फाइनल मुकाबले में हरियाणा की उस शैफाली वर्मा ने करिश्माई पारी खेली, जो विश्व कप के शुरू होने से पहले टीम का हिस्सा भी नहीं थी। उसने अपने चयन को तार्किक साबित किया। इसी तरह दीप्ति शर्मा ने भी शानदार खेल का परिचय दिया। निश्चय ही महिला क्रिकेट टीम की यह शानदार जीत देश की उन लाखों बेटियों के सपनों को नयी ऊंचाइयां देगी, जो अपना आसमान हासिल करना चाहती हैं। निस्संदेह, विश्वकप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत के दूरगामी परिणाम होंगे। इस खेल में टीम दीर्घकालिक वर्चस्व कायम रख सकती है। दरअसल, अब तक महिला क्रिकेट को दोयम दर्जे का माना जाता रहा है। दरअसल, जब से महिला खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के समान वेतन मिलने लगा और उन्हें आईपीएल-शैली की टी-20 लीग में दमखम दिखाने का मौका मिला, टीम के प्रदर्शन में अभूतपूर्व सुधार आया। धीरे-धीरे वे पुरुष क्रिकेट के सितारों की तरह आभा बिखेरने लगी। हालांकि, आगे की राह इतनी भी आसान नहीं है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल उनके पास इस कामयाबी का जश्न मनाने का मौका है। उल्लेखनीय है कि टीम में कई ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने तमाम आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों का मुकाबला करके अपनी जगह बनायी। वे तपती पगडंडियों से गुजरने वाली बेटियों के लिये प्रेरणास्रोत हैं। इन खिलाड़ियों ने मैदान से पहले निजी जीवन में बड़ा संघर्ष किया। बेहद जटिल पृष्ठभूमि से आने के बावजूद वे विश्व विजेता टीम का हिस्सा बनी हैं। उनके साथ अभ्यास मैच खेलने के लिये लड़कियां नहीं होती थी, अतः वे शुरुआती क्रिकेट लड़कों की टीम के साथ खेलती थीं। उनके माता-पिता को समाज की छींटाकशी का भी शिकार होना पड़ता था। मध्यप्रदेश की क्रांति गौड़ ने आर्थिक बदहाली का जीवन जिया और प्रैक्टिस मैच के लिये पैसे की मदद न मिलने पर मां ने गहने तक बेचने पड़े। वक्त बदला है और आज मध्य प्रदेश सरकार ने उसे एक करोड़ का पुरस्कार देने की घोषणा की है। स्पिनर राधा यादव का परिवार मुंबई के कांदिवली में रहता है और उसके पिता सब्जी बेचते रहे हैं। उनकी प्रतिभा पहचानकर क्रिकेटर प्रफुल्ल नाइक ने उसके परिजनों को क्रिकेट खेलने के लिये मनाया। संगरूर जिले की रहने वाली सफल गेंदबाज अमनजोत के, पेशे से कारपेंटर पिता भूपेंदर सिंह ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने अपना कामधंधा दांव पर लगाया। इसी तरह हिमाचल के एक किसान परिवार से आने वाली तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर ने अपने दिवंगत पिता के सपने को पूरा किया। निस्संदेह, इन लड़कियों की कामयाबी न केवल समाज में लड़कियों के प्रति नजरिया बदलेगी, बल्कि उन जैसी लाखों लड़कियों को क्रिकेट में भविष्य आजमाने के लिये भी प्रेरित करेगी।

विकासशील देशों के सामने एआई संप्रभुता की चुनौती

> किसी भी स्थिति में, एआई संप्रभुता आज कई मध्यम-आय वर्ग के देशों के लिए एक दुखती रग साबित हो रही है। उन्हें वित्तीय निवेश करने की अपनी क्षमता का आकलन, अपेक्षित आर्थिक लाभ, डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने होंगे।

अब जबकि हमारा देश 'भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026' आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि फरवरी माह में पेरिस में हुए एआई क्रियान्वयन शिखर सम्मेलन 2025 में एआई संप्रभुता एक केंद्रीय मुद्दा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज दुनियाभर में एआई से संबंधित बड़े पैमाने पर निवेश की दिशा-दशा एआई संप्रभुता की अवधारणा निर्धारित करती है।

डिजिटल युग के आरंभिक और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक, फ्रांसीसी दार्शनिक बर्नार्ड स्टीगलर के अनुसार, तकनीक की पारंपरिक अवधारणा से आगे बढ़ने में दुनिया को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। उनका मानना था कि 'मनो-राजनीति' (साइकलोपॉलिटिक्स), जो, मीडिया और तकनीक हमारे मानस और ध्यान को आकार देने की क्षमता रखती है, 21वीं सदी को परिभाषित करती है। स्टीग्लर का तर्क था कि तकनीक एक 'फार्माकोन' है– ज़हर जो इलाज भी करता है - और यह हमें चुनना होगा कि हम तकनीक को अपना 'इस्तेमाल' करने दें या आधुनिक एजेंसियों से अपनी तर्कसंगत संप्रभुता वापस पाने के लिए इसका उपयोग 'महत्वपूर्ण गहनता' के लिए सावधानी से करें।

हालांकि, 21वीं सदी की शुरुआत में 'तकनीकी संप्रभुता' की अवधारणा का पुनर्विन्यास हुआ था, जो मुख्यतः भू-राजनीतिक टकरावों और प्रतिबंधों के परिणामवश था। वर्ष 2000 और 2010 के दशक की शुरुआत में, इंटरनेट संप्रभुता पर सबसे पहले चर्चा संभवतः चीन में हुई थी। फिर, इस एआई युग में विदेशी शक्तियों पर निर्भरता से बचने के लिए, विभिन्न देशों ने डिजिटल बुनियादी ढांचा, डेटा और एआई पर नियंत्रण स्थापित किया। साथ ही, ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में 2018 में अमेरिका और चीन के बीच चले व्यापार युद्ध ने संप्रभु एआई होने की जरूरत को बढ़ावा दिया।

एआई संप्रभुता किसी राष्ट्र या कंपनी द्वारा अपनी एआई तकनीकों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने की क्षमता है, जिसमें डाटा, बुनियादी ढांचा और स्वरूप शामिल हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, नियामक अनुपालन और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। इसमें विदेशी नियंत्रण केंद्रों पर निर्भरता से बचना, संवेदनशील डाटा को अपने अधिकार क्षेत्र में बनाए रखना और घरेलू ढांचे के भीतर एआई प्रणालियों का विकास एवं कार्यान्वयन शामिल है। सरल शब्दों में, संप्रभु एआई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि एआई का उत्पादन घरेलू स्तर पर हो, जिसमें वह डेटा भी शामिल हो जिसका उपयोग एआई प्रशिक्षण में, अनुसंधान करते वक्त खोज करने में और किसी प्रश्न के उत्तर में आउटपुट के रूप में उत्पन्न करने वाला डाटा हो। इस प्रकार, 'डेटा संप्रभुता' और 'एआई संप्रभुता' आपस में जुड़ी हुई हैं, फिर भी अलग हैं। लेकिन संप्रभु एआई यह सुनिश्चित करता है कि एआई उनके सांस्कृतिक, नैतिक और कानूनी मानकों के अनुरूप हो।

आज राष्ट्रों को जेनएआई के जोखिमों, फायदों और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में मालूम है। उदाहरण के लिए, 2035 तक, एआई भारत की अर्थव्यवस्था को 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। अप्रैल 2024 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के एक लेख में, जिसका शीर्षक है 'संप्रभु एआईः यह क्या है, और इसकी प्राप्ति के छह रणनीतिक स्तंभ', के अनुसार, संप्रभु एआई के लिए प्रयास का अर्थ अनिवार्य रूप से डिजिटल अलगाव नहीं है, बल्कि रणनीतिक लचीलेपन के लिए प्रयास है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मिलकर किया जा सकता है। रणनीतिक स्तंभ, जिनमें डिजिटल बुनियादी ढांचा, कार्यबल विकास, अनुसंधान, विकास एवं नवाचार, नियामक एवं नैतिक तानाबाना, एआई उद्योग को प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं, ये अवयव देशों को अपनी संप्रभु एआई क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिए, संप्रभु एआई का मार्ग जटिल है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सावधानीपूर्वक, दीर्घकालिक रणनीतिक योजना की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न देशों में संप्रभु एआई के उदाहरणों में, सिंगापुर में एक सरकारी-वित्त पोषित एआई मॉडल मौजूद है, जो ग्यारह विभिन्न भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है; मलेशिया का आईएलएमयूचैट मॉडल, जिसे एक स्थानीय निर्माण कंपनी ने बनाया है; और स्विट्ज़रलैंड में 'एपर्टस',तो दक्षिण कोरिया ने कोरियाई भाषा और डाटा आधारित 'संप्रभु एआई' के निर्माण के लिए 735 बिलियन डॉलर खर्च करने का इरादा किया है। भारत में, मार्च 2024 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत 'भारत में एआई का निर्माण और भारत के लिए एआई को उपयोगी बनाने' के उद्देश्य से 38,000 जीपीयू तैनात करके पांच वर्षों में 10,300 करोड़ से अधिक आवंटित किए जाने हैं।

एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने 2024 की शुरुआत में घोषणा की थी कि 'हर देश को संप्रभु एआई की आवश्यकता है'। एआई संप्रभुता की वैश्विक दौड़ के बीच गौर करने लायक है कि संप्रभु एआई सेवाएं मुख्यतः अमेरिकी और चीन की चंद बड़ी तकनीकी विशेषज्ञता वाली कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। दुनिया के देश अक्सर बुनियादी ढांचे और चिप्स के लिए अधिकांशतः उन पर दीर्घकालिक निर्भरता के लिए मजबूर हैं। ये बड़ी तकनीकी कंपनियां संप्रभुता को एक सेवा के रूप में प्रदान करके, संप्रभु प्रौद्योगिकी से जुड़े विमर्श को प्रभावित कर रही हैं। एनवीडिया ने इस विश्वव्यापी बुनियादी ढांचे को बनाने वाले हिस्सों को 'एआई फ़ैक्टरी' का नाम दिया है। और यह दुनिया भर के देशों में चिप्स और हार्डवेयर बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का अनुबंध यूएई और अन्य देशों के साथ है। अमेज़न वेब सर्विसेज़ 'एडब्ल्यूएस यूरोपियन सॉवरेन क्लाउड' प्रदान करता है। निजी व्यवसाय भी माइक्रोसॉफ्ट के एज़्यूर और गूगल क्लाउड से सॉवरेन क्लाउड का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें डेटा स्थानीयकरण और एन्क्रिप्शन शामिल है।

हालांकि, ऐसी 'संप्रभुता को सेवा के रूप में' प्रस्तुत करने को औपनिवेशिक राज का एक समकालीन संस्करण बताने वाली बयानबाज़ी भी शुरू हो गई। उदाहरण के लिए, जून, 2025 में लंदन रिव्यू ऑफ़ बुक्स में प्रकाशित लालेह खलीली के 'सामूहिक संपत्ति, निजी नियंत्रण' शीर्षक वाले लेख में इसका वर्णन किया गया है। पुराने समय में, 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा औपनिवेशिक विस्तार के साधन के रूप में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) योजनाओं का उपयोग किया जाता था। जिसके तहत निजी,महानगरीय कंपनियां सड़क, रेलमार्ग, बंदरगाह, नहर, टेलीग्राफ लाइन आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए जरूरत का धन, विशेषज्ञता और संसाधन प्रदान करती थीं। उपनिवेशों या उन जगहों पर जहां उनकी सरकार अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही हो। हालांकि, यह एआई संप्रभुता के वर्तमान परिदृश्य से कितना मिलता-जुलता है और कहां पर भिन्न हैं, यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं नई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के घटकों पर निर्भर है।

बहरहाल, अब हर जगह की सरकारें किसी न किसी तरह से अपनी खुद की 'संप्रभु' एआई तकनीक बनाने पर अरबों खर्च करने के लिए मजबूर हैं। इसके कुछ प्रस्तावित विकल्प भी हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन की दिग्गज कंपनियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वंद्वी विकसित करने के लिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बेनेट स्कूल फॉर पब्लिक पॉलिसी के शोधकर्ताओं ने एक सार्वजनिक एआई कंपनी बनाने का सुझाव दिया है, जिस पर आने वाला खर्च मध्यम-आय वाले देशों के समूह मिलजुल कर उठाएं।

किसी भी स्थिति में, एआई संप्रभुता आज कई मध्यम-आय वर्ग के देशों के लिए एक दुखती रग साबित हो रही है। उन्हें वित्तीय निवेश करने की अपनी क्षमता का आकलन, अपेक्षित आर्थिक लाभ, डेटा गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने होंगे।

प्रेरणा

विनम्रता का प्रकाश

युवावस्था में बेंजामिन फ्रैंकलिन की बुद्धि किसी तीर की तरह तेज थी—जहाँ बैठते, वहीं अपनी चमक और तर्क से लोगों को प्रभावित कर देते। उनकी बातों में दम था, विचारों में तेजी थी, और मन में यह विश्वास कि वे हर चर्चा को अपनी दिशा में मोड़ सकते हैं। पर इसी तेजस्विता के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार भी था, जो उन्हें महसूस नहीं होता था, पर आसपास के लोग साफ देख लेते थे।

एक दिन उनके एक बुजुर्ग मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, "बेंजामिन, तुम्हारी वाणी में आग है, पर दीपक की रोशनी नहीं।" यह वाक्य फ्रैंकलिन के भीतर जैसे सीधे उतर गया। वे चौंके, फिर गंभीरता से बोले, "इसका क्या अर्थ है?" तब उनके मित्र ने बहुत कोमल स्वर में कहा, "जो हर समय बहस में जीतना चाहता है, वह लोगों के दिलों में हार जाता है। ज्ञान तब तक अधूरा है, जब तक उसमें विनम्रता का रंग न हो।"

इन शब्दों ने फ्रैंकलिन को भीतर से हिला दिया। वह पहली बार समझ पाए कि बुद्धिमत्ता केवल जिताने का साधन नहीं, जोड़ने का भी मार्ग है। उसी रात उन्होंने अपनी व्यक्तिगत डायरी में एक संकल्प लिखा—"मैं बोलने से अधिक सुनूंगा। मैं अपनी वाणी से आग नहीं, प्रकाश फैलाऊंगा।" यह वाक्य सिर्फ लिखे नहीं गए थे, बल्कि उनके जीवन का नया

अध्याय बन चुके थे।

कुछ महीनों बाद, संसद में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक थी। देश की दिशा तय होने वाली थी और कई नेता अपने-अपने विचार लेकर खड़े थे। लेकिन माहौल समाधान का नहीं, टकराव का था। हर कोई दूसरे की बात काट रहा था, अपनी आवाज़ ऊँची कर रहा था, और बैठक एक ऐसी नाव बन गई थी जो तूफान में बिना पतवार डोल रही हो।

फ्रैंकलिन उस दिन असामान्य रूप से शांत थे। उन्होंने किसी की बात नहीं काटी। वे बस सुनते रहे—हर तर्क, हर चिंता, हर असहमति। जहाँ बाकी लोग ऊँची आवाज़ें लेकर खड़े थे, वहाँ वे मौन होकर सबको जगह दे रहे थे। उनके इस मौन में भी एक गहरी उपस्थिति थी, जिसे कमरे के हर व्यक्ति ने महसूस किया।

आखिरकार जब सब थककर चुप हो गए, तब फ्रैंकलिन ने बहुत धीमे स्वर में कहा,

"यदि हम एक-दूसरे की बात सुन लें तो समाधान हमसे नहीं, बल्कि स्वयं परिस्थिति से जन्म लेता है। हम ज्ञानवान बन सकते हैं, पर बुद्धिमान तभी बनते हैं जब सुनना सीखते हैं।"

उनकी वाणी में इस बार न तेज़ी थी, न चुनौती—केवल शांत प्रकाश, जैसे कोई दीपक अंधेरे कमरे में रखा हो। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। लोग पहली बार समझ पाए कि सबसे प्रभावशाली विचार वही होते हैं, जिनके पीछे विनम्रता का स्पर्श होता है। बैठक समाप्त होने पर एक वरिष्ठ नेता उनके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा,

"मैंने अनेक वक्ताओं को सुना है—जो जोर से बोलते हैं, जो प्रभावशाली तर्क रखते हैं, पर आज पहली बार सुना कि आवाज़ केवल तब महान बनती है जब वह चिल्लाती नहीं, बल्कि समझाती है। आज आपने यह सिखा दिया कि शांत मन से बोलना भी नेतृत्व है।"

फ्रैंकलिन मुस्कुराए और बोले,

"विनम्रता बुद्धि का द्वार है। और सुनना सीखने की पहली सीढ़ी। जब हम भीतर से शांत होते हैं, तभी बाहर प्रकाश फैलता है।"

यह घटना उनके जीवन की दिशा बदल गई। उस दिन के बाद लोग फ्रैंकलिन को सिर्फ एक तेज दिमाग वाला युवक नहीं, बल्कि एक शांत और संतुलित बुद्धिमान व्यक्ति मानने लगे। उनकी वाणी पहले की तरह तेज जरूर रही, पर अब उसमें चिंगारियाँ नहीं, रोशनी थी। और यही रोशनी आगे चलकर उन्हें इतिहास के महानतम विचारकों में शामिल कर गई।

इस कथा का सार यही है कि
ज्ञान तब स्वयं दीपक बन जाता है, जब उसके भीतर विनम्रता की बाती हो और सुनने का तेल हो। बोलना एक कला है, पर सुनना एक साधना।

हिंदी में शपथ : नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष

भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक चेतना का नया शुभारंभ है। यह वह क्षण है जिसने भाषा को लेकर दशकों से चले आ रहे संकीर्ण विवादों, राजनीतिक विरोधाभासों और कृत्रिम विभाजनों पर एक गहरी चोट की है। हिंदी में शपथ का यह निर्णय राष्ट्रीय मानस में इस भावना को पुनः स्थापित करता है कि भाषा का प्रश्न केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। यह निर्णय उस विरोधाभास पर भी प्रकाश डालता है जिसमें विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी को अपने ही देश में सबसे अधिक उपेक्षा, संकोच और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता रहा है। भारत में भाषा सदैव राजनीति का एक सुविधाजनक औज़ार रही है। कुछ दशकों से चले आ रहे भाषाई आंदोलन और हिंदी-विरोधी राजनीति ने देश की एकता को अक्सर चुनौती दी है। क्षेत्रवाद की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदी को एक क्षेत्र विशेष की भाषा बताकर उसका महत्व कम करने का प्रयास किया। लेकिन यह तर्क न तो व्यावहारिक था और न ही ऐतिहासिक। हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय की भाषा है, जनमानस की अभिव्यक्ति है, भारत की आत्मा की धड़कन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना इस सत्य को पुनः उद्घाटित करता है कि भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएँ केवल कानून और प्रशासन की रक्षा ही नहीं करतीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीय अस्मिता को भी नई दिशा देती हैं। यह कदम यह संदेश देता है कि नई पीढ़ी की संस्थाएँ अब संकोच नहीं, आत्मविश्वास के साथ भारत की भाषा में अपने कर्तव्यों की शुरुआत कर रही हैं।

हिंदी को लेकर जो विरोधाभास पैदा किया जाता रहा है, वह वास्तव में एक कृत्रिम एवं आग्रह-दुराग्रहपूर्ण द्वंद्व है। आज के वैश्विक दौर में भाषा का महत्व उसकी लोकस्वीकृति और उपयोगिता से तय होता है। हिंदी वैश्विक भाषाओं की सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रही है। करीब 113 करोड़ के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है. 111 करोड़ के साथ चीनी दूसरे स्थान पर है, इसके बाद हिन्दी का स्थान आता है। करीब 61.5 करोड़ विश्व में, हिन्दी को बोलने वाल लोगों की संख्या के आधार पर तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी का प्रभाव विश्व में बढ़ रहा है और यह सोशल मीडिया व संचार माध्यमों में भी लगातार उपयोग हो रही है। दुनिया भर के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। भारत सरकार की पहल के बाद से, संयुक्त राष्ट्र ने भी साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन शुरू किया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मोरिशस, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों और यूरोप में हिंदी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य, भाषाविज्ञान और अनुवाद अध्ययन का विस्तार हुआ है। हिंदी फिल्में, वेब प्लेटफॉर्म और मीडिया विश्व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह वह समय है जब हिंदी वैश्विक मंच पर उभर रही है, लेकिन अपने ही देश में उसे राजनीति और संकीर्णताओं का शिकार होना पड़ रहा है। यही वह असंगति है जिसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत की शपथ ने बड़े सौम्य किंतु तीव्र संदेश के साथ उजागर किया है कि जब दुनिया हिंदी को सम्मान दे रही है तो भारत में उसकी उपेक्षा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय प्रतीक केवल वस्तुएँ नहीं होते, वे राष्ट्र की चेतना के वाहक होते हैं। राष्ट्रध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रगान केवल धुन नहीं, बल्कि भारत की समष्टिगत भावना का सूत्र है। उसी प्रकार राष्ट्र की भाषा-चाहे उसे हम राजभाषा कहें या राष्ट्रभाषा भारतीय पहचान और राष्ट्रीय एकता का अदृश्य धागा है। नए भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम इन प्रतीकों का सम्मान केवल संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि हृदय में करें। हिंदी को लेकर जो संकोच, झिझक और कृत्रिम विरोध दशकों से बना हुआ था, वह राष्ट्रीय आत्मविश्वास के लिए बाधक था। हिंदी में शपथ लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मानसिक दरार को पाटने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का साहसिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर ब्रिक्स, जी-20 और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हिंदी में संबोधन देकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी भाषा को लेकर हिचकता नहीं, बल्कि गर्व करता है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की थी। उनकी वाणी में हिंदी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की ध्वनि थी। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को राष्ट्रीयता, आधुनिकता, आत्मविश्वास और वैश्विक उपस्थिति के साथ आगे बढ़ाया है। उन्हें यह समझ थी कि भाषा राष्ट्रीय चेतना की नींव होती है, और जिस राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की आकांक्षा है, उसे अपनी भाषा पर गर्व करना ही होगा। जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपनी भाषा को वैश्विक मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाता है और जब राष्ट्र का प्रधान न्यायाधीश उसी भाषा में शपथ लेता है, तब यह संकेत मिलता है कि नए भारत की भाषा नीति संकोच नहीं, बल्कि स्वाभाविक भारतीयता की पुनर्स्थापना है। हिंदी केवल भावनात्मक आग्रह नहीं है। यह शासन, न्याय, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और तकनीक की भाषा बनती जा रही है। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकी क्रांति में हिंदी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आज इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में हिंदी शीर्ष पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन अनुवाद और डिजिटल पत्रकारिता में हिंदी का उपयोग बढ़ाना भारत की ज्ञान-आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी भाषाई आत्मनिर्भरता पर भी निर्भर करती है। जितनी अपनी भाषा मजबूत होगी, उतना ही विचार-निर्माण, नवाचार और जनसक्रियता मजबूत होगी। इस दृष्टि से हिंदी के प्रति उपेक्षा केवल सांस्कृतिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास को बाधित करने वाला संकीर्ण एवं राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण भी है।

अभियान

नारद का दर्प और भगवान की माया का अद्भुत लीला–प्रसंग

नारद मुनि उस समय अहंकार के ऐसे अश्व पर सवार थे जिसकी गति का अनुमान देवता भी न लगा सकें। यह अश्व चलता नहीं, उड़ता था—और वह भी इतना ऊँचा, इतना तीव्र कि स्वयं गरुड़ भी उसकी उड़ान देखकर विस्मित हो जाएँ। यह केवल गति नहीं थी, यह मुनि के भीतर जन्मा वह गर्व था जिसे स्वयं नारद भी पहचान नहीं पा रहे थे। उनके मन में यह बात बैठ चुकी थी कि कामदेव को परास्त करने वाला, सभी लोकों में विचरण करने वाला, और अपनी वाणी से सत्पथ का उपदेश देने वाला उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं।

भगवान विष्णु बैकुण्ठ से इस संपूर्ण नाटक को देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर निश्चय किया—"यह अहंकार यदि इसी प्रकार बढ़ता रहा, तो मुनि स्वयं अपने धर्म से विचलित हो जाएँगे। अब समय आ गया है कि उन्हें उनकी सीमाएँ याद दिलाई जाएँ।" भगवान का संकल्प लीला का प्रारम्भ था और मुनि का अहंकार उसका केंद्र।

नारद बैकुण्ठ पहुँचे। भगवान ने उन्हें वैसे कठोर उपदेश नहीं दिए जैसे महादेव ने दिए थे। नारद के मन में यह बात तुरंत घर कर गई—"भगवान विष्णु ने मेरी महत्ता को पहचाना है। उन्होंने मेरी प्रशंसा में

मौन स्वीकार कर लिया है।" इस स्वीकार को मुनि अहंकार समझें या आशीर्वाद, यह भ्रम उन्हें सुख देता रहा।

वे भगवान को प्रणाम कर बैकुण्ठ से प्रसन्न होकर लौटे—परंतु उन्हें पता ही न था कि उनके रास्ते में एक दिव्य जाल फैला दिया गया है। एक ऐसा जाल जो माया से नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपी उस कमजोरी से बना था, जो अब जागने वाली थी।

भगवान विष्णु ने उसी मार्ग पर एक अनुपम माया–नगरी का निर्माण किया। उसकी चमक बैकुण्ठ से भी अधिक थी। स्वर्ण, रत्न, मोती, संगीत, सुगंध, सौंदर्य—सब कुछ वहाँ अपनी सीमा से परे था। कोई भी देवता उसे देख ले, तो सोचने लगे कि यह स्थान स्वर्ग से ऊपर किस दिव्यता का है। उस नगरी का राजा था—शीलनिधि। यशस्वी, तेजस्वी, शूरवीर और सौ इन्द्रों के समान ऐश्वर्य वाला। उसकी एक पुत्री थी—विश्वमोहिनी। नाम जैसा, रूप वैसा। ऐसी सुंदरता कि स्वयं लक्ष्मीजी भी उसे देखकर चकित हो जाएँ। उसकी आँखें कमल के समान, वाणी मधुमक्खी की गुंजन जैसी मधुर, और चाल ऐसी जैसे सृष्टि की लय उसी से संचालित हो।

नगर में भीड़ थी—दूर–दूर से आए राजा, महाराजा, योद्धा—सब विश्वमोहिनी के स्वयंवर में भाग लेने आए थे। चारों ओर गंधर्व–गीत, पुष्पों की वर्षा और उत्सव की गूंज। नारद ने यह नगर देखा तो पहले ही क्षण में चकित रह गए। उन्होंने सोचा—"मैं तो अनगिनत बार इस मार्ग से गुज़रा हूँ, पर ऐसा विलक्षण नगर कभी तो नहीं दिखा? अवश्य कोई विशेष बात है।"

वे नगर में प्रवेश कर गए। नगरवासियों ने उन्हें आदर दिया, राजा ने चरण पखारे, आसन दिया, और पूरा सम्मान किया। नारद के भीतर अहंकार की लहर एक बार फिर उठी—

"देखो! मैंने कामदेव को परास्त किया और अब संसार मेरे चरणों में है।"

तभी राजा ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को बुलाया।

जैसे ही विश्वमोहिनी ने प्रांगण में प्रवेश किया, नारद मुनि क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आँखें अपलक हो गईं। जिसने कामदेव को परास्त किया था, वह आज काम के अदृश्य बाणों से घायल हो उठा। उन्होंने उसके लक्षण देखे, हस्तरेखाएँ देखीं—और उनके भीतर कोई गुप्त ज्वाला जल उठी।

उसकी हस्तरेखाओं में कुछ ऐसा लिखा था जिसने उनके मन में एक गहरा आकर्षण जगा दिया।

मुनि के चेहरे पर आनंद था, पर वे दिखा नहीं रहे थे।

हृदय भीतर नाच रहा था, पर चेहरा संत की तरह शांत था।

अब अहंकार का दूसरा रूप प्रकट हुआ—"कामदेव को हराया, अब विश्वमोहिनी जैसी कन्या भी मेरे भाग्य में हो सकती है।" देवर्षि नर–नारी दोनों के मन को पढ़ सकते थे, पर इस समय वे अपने मन के मोह को पढ़ ही नहीं पाए।

उन्हें यह भ्रम हो गया कि विश्वमोहिनी के लक्षणों में जिस सौभाग्य का संकेत उन्होंने देखा है, वह उनके लिए ही लिखा है।

उनके भीतर एक मीठी–सी तृष्णा जागने लगी।

परंतु माया की नगरी में जो चमक थी, जो सौंदर्य था, जो भाग्य की चमक थी—वह सब भगवान विष्णु के जाल का ताना–बाना था।

अब प्रश्न यही है—

विश्वमोहिनी की उन हस्तरेखाओं में ऐसा क्या लिखा था जिसने नारद के मन में मोह, वासना, गर्व और आकांक्षा—सभी को एक साथ जगा दिया?

कौन–सा भविष्य उसके हाथ में लिखा था जिसने मुनि को यह विश्वास दिला दिया कि उसका स्वयंवर किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं उनके लिए ही है?

यही से मुनि की परीक्षा शुरू होती है, और भगवान की लीला अपनी सबसे विचित्र पराकाष्ठा पर पहुँचने वाली है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

कच्छ-सौराष्ट्र के कच्छी छुहारे और केसर आम से लेकर हस्तकला तथा हाथबुनाई काम के 10 से अधिक उत्पादों ने प्राप्त किया है जीआई टैग

▸▸ वीजीआरसी कच्छ-सौराष्ट्र जीआई टैग उत्पादों को प्रमोट करेगी और स्थानीय कारीगरों को सशक्त करेगी
▸▸ वीजीआरसी निर्यात क्षमताओं में वृद्धि करेगी तथा प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' विजन को वेग देगी

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव देश के स्थानीय एवं वंश-परंपरागत उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित किया है। स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत जियोग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग वाले उत्पादों को सक्रिय प्रोत्साहन दिया है और इन उत्पादों को सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक सशक्तिकरण तथा वैश्विक मान्यता के साथ जोड़ा है। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में भी बार-बार इन उत्पादों का उल्लेख किया है तथा कारीगरों को व्यक्तिगत रूप से जीआई सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं।

उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 'विकास भी, विरासत भी' के विजन के साथ 2030 तक भारत में 10,000 जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग वाले उत्पादों तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है। जीआई टैगिंग जैसी पहल द्वारा राज्य के कारीगरों तथा किसानों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए गुजरात कच्छ के विख्यात कपड़े से लेकर सौराष्ट्र के प्रीमियम उत्पादों तक की अपनी विरासत को प्रमोट कर रहा है, जिससे राज्य वैश्विक स्तर पर आत्मनिर्भर बने। जीआई उत्पादों का संरक्षण तथा उनका प्रमोशन 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के सिद्धांत पर बल देता है, जो स्थानीय क्षमताओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में परिवर्तित करता है। कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र ने अजरख, बांधणी (बंधेज), रोगन क्राफ्ट पेंटिंग, कच्छी शॉल, कच्छी छुहारा और केसर आम जैसे विख्यात उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त किए हैं, जो स्थानीय कारीगरों का विकास करते हैं और उन्हें वैश्विक पहचान देते हैं। राजकोट में आयोजित होने वाली आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) कच्छ-सौराष्ट्र के हस्तकला तथा हाथबुनाई कारीगरों की स्थानीय श्रेष्ठता एवं निर्यात संभावना को उजागर करने के लिए सज्ज है।

परंपरा तथा कलात्मकता से समृद्ध, गुजरात के कच्छ तथा सौराष्ट्र प्रदेशों ने उनकी सांस्कृतिक एवं कृषि विरासत को प्रस्तुत करने वाले उत्पादों के लिए 10 से अधिक जीआई मान्यताएँ प्राप्त की हैं। कच्छ के विख्यात उत्पादों में भरतकाम (कशीदाकारी), अजरख, ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधणी टाई-डाई, रोगन क्राफ्ट पेंटिंग तथा कच्छी शॉल शामिल हैं। इसके अलावा; कृषि उत्पादों की बात करें, तो कच्छी छुहारे को भी जीआई टैग दिया गया है, जो उसके अद्भुत स्वाद एवं पोषक तत्वों से भरपूर गुणवत्ता के लिए विख्यात है। सौराष्ट्र के विशिष्ट उत्पादों में गीर का केसर आम, जो गीर प्रदेश में 'आम की रानी' के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जामनगरी बांधणी तथा राजकोट पटोळा रेशम बुनाई शामिल हैं। ये जामनगरी बांधणी तथा राजकोट की साड़ियाँ कई बॉलीवुड हस्तियों के वॉर्डरोब में भी स्थान पा चुकी हैं।

इतना ही नहीं; सुरेन्द्रनगर की टांगलिया शॉल भी उसकी विशिष्ट वस्त्र कला का नमूना है, जिसने कला के उत्साहियों को आकर्षित किया है तथा एक वैश्विक मांग खड़ी की है।

सौराष्ट्र तथा कच्छ क्षेत्र में आयोजित होने वाली वीजीआरसी इस क्षेत्र की हस्तकला तथा हाथबुनाई कारीगरों की क्षमता को वेग देगी। यह दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस हेरिटेज क्षेत्र के उद्यमियों, कारीगरों, इंटीरियर डिजाइनर्स तथा प्रोडक्ट डिजाइनर्स के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस, निवेशकों, निजी उद्यमों तथा अग्रणी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करने के लिए एक गतिशील प्लेटफॉर्म के रूप में सेवा देती है, जो नवीनीकरण, बाजार पहुँच तथा टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देता है।

गांधीधाम का गवरमेंट डीजल लोको मेंटेनेस शेड : देश ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उच्च-क्षमता मेंटेनेंस केंद्रों में शामिल

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेदप्रकाश ने गांधीधाम स्थित अत्याधुनिक (GDLG) गवरमेंट डीज़ल लोको मेंटेनेंस शेड का निरीक्षण किया। मिठीरोहर के निकट स्थित यह शेड भारतीय रेल के सबसे महत्वपूर्ण मेंटेनेंस केंद्रों में से एक है, जहाँ उच्च क्षमता वाले 250 लोकोमोटिव का विश्वस्तरीय रखरखाव किया जाता है। निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री वेदप्रकाश ने शेड की सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली, साफ-सुथरे वातावरण, उन्नत तकनीकी सुविधाओं तथा कर्मचारी-क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि "यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा शेड है, जहाँ इतनी योजना, गुणवत्ता और दक्षता के साथ हाई हॉर्सपावर इंजनों का मेंटेनेंस किया जाता है। यहाँ न ऑयल लीकेज है और न ही किसी प्रकार की गंदगी — यह वास्तव में भारतीय रेल के लिए दिशा-निर्देशक मॉडल है।"

उच्च क्षमता और अत्याधुनिक व्यवस्था

▸▸ इस शेड की क्षमता कुल 250 लोकोमोटिव (213 लोको – 4500 HP, 37 लोको – 6000 HP) के नियमित मेंटेनेंस की है।

▸▸ लोकोमोटिव यहां से निकलकर पूरे देश में 95,000 किमी तक बिना किसी प्रमुख समस्या के लगातार संचालित रहते हैं।

▸▸ 6 ट्रैक वाले इस शेड में नियमित रूप से 5 लाइनों का उपयोग होता है। हर लाइन पर क्रेन प्रणाली उपलब्ध है, जिससे किसी भी लाइन पर किसी भी समय कार्य आसानी से किया जा सकता है।

▸▸ यह शेड 1,19,437.500 वर्ग मीटर (29.513 एकड़) क्षेत्र में विकसित किया गया है और देश के अन्य शेड से बिल्कुल अलग, योजनाबद्ध लेआउट रखता है।

प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स और ऑनलाइन मॉनिटरिंग

शेड में 24x7 उपलब्ध प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स टीम (PRT) और हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी लोकोमोटिव में आई समस्या पर त्वरित तकनीकी सहायता दी जाती है। ट्रेन चालक को रास्ते में किसी कठिनाई का सामना होने पर सीधे गांधीधाम शेड से ही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

यहाँ इंजनों का मेंटेनेंस उतने ही समय में पूरा कर दिया जाता है, जितना समय कंडला-मुंद्रा बंदरगाह पर लोडिंग-अनलोडिंग में लगता है, जिससे माल ढुलाई की दक्षता कई गुना बढ़ती है।

आधुनिक सुरक्षा एवं संरक्षा प्रणाली

शेड में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

▸▸ 7.5 लाख लीटर जल भंडारण क्षमता
▸▸ अत्याधुनिक फायरफाइटिंग सिस्टम
▸▸ ऑटो मोड पंपिंग सुविधा
▸▸ पूरे परिसर में फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और केंद्रीय मॉनिटरिंग तंत्र
▸▸ ऑन-साइट प्राथमिक उपचार केंद्र और एम्बुलेंस

इस शेड के संचालन से स्थानीय स्तर पर लगभग 500 लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है, जिससे कच्छ क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है।

तकनीकी विशेषताएँ – WDG4G एवं WDG6G लोकोमोटिव

शेड में रखरखाव किए जाने वाले WDG4G एवं WDG6G लोकोमोटिव आधुनिक तकनीक, पर्यावरण-अनुकूल उत्सर्जन मानकों और उच्च हॉर्सपावर क्षमताओं से युक्त हैं।

▸▸ WDG4G (4500 HP) – GEVO-12 इंजन आधारित
▸▸ WDG6G (6000 HP) – GEVO-16 इंजन आधारित

दोनों ही मॉडल UIC-1 उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं और 100 किमी/घंटा की अधिकतम गति के साथ उच्चतम ट्रैक्टिव क्षमता प्रदान करते हैं।

यह परियोजना 30 नवंबर 2015 को भारतीय रेल और निजी भागीदार के बीच हुए प्रोक्योरमेंट-कम-मेन्टेनेंस एग्रीमेंट (PCMA) के तहत अस्तित्व में आई। यह भारतीय रेल में पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आधारित परियोजनाओं में से एक है। बाद में इस संयुक्त उद्यम का नाम 27 सितंबर 2021 को बदलकर वैबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया।

गांधीधाम का GDLG लोको शेड भारतीय रेल के तकनीकी आधुनिकीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। सुव्यवस्थित प्रक्रियाएँ, स्वच्छ परिसर, उच्च क्षमता वाले लोकोमोटिव, त्वरित तकनीकी सहायता और पूर्ण सुरक्षा प्रणाली — ये सभी कारक इसे न केवल भारत का, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ मेंटेनेंस डिपो बनाते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद ने गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) के साथ बैठक की

(जीएनएस) पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा गांधीधाम में गांधीधाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक एवं संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने की। इस बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों, व्यापारिक संस्थाओं तथा विभिन्न हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और रेल परिवहन को अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अपने सुझाव एवं अपेक्षाएँ साझा कीं।

कच्छ औद्योगिक कॉरिडोर से 50 MT से अधिक माल परिवहन का लक्ष्य

बैठक का मुख्य फोकस कच्छ औद्योगिक क्षेत्र से 50 मिलियन टन से अधिक माल परिवहन के लक्ष्य को मजबूती देना था। श्री प्रकाश ने बताया कि पश्चिम रेलवे उद्योग जगत के साथ साझेदारी को और मजबूत करते हुए लॉजिस्टिक्स को तेज़, विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

अहमदाबाद मंडल और गांधीधाम सब-डिवीजन की उत्कृष्ट उपलब्धियाँ

▸▸ वर्ष 2025-26 के पहले सात माह में 29.18 मिलियन टन माल परिवहन का उल्लेखनीय कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

▸▸ इसी अवधि में 3.865 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

▸▸ इनमें से 22.77 मिलियन टन माल परिवहन गांधीधाम क्षेत्र से हुआ, जो कच्छ के उद्योग जगत और रेलवे के बीच मजबूत तालमेल का प्रतीक है।

श्री प्रकाश ने इन उपलब्धियों के लिए संपूर्ण रेलवे परिवार तथा व्यापारिक समुदाय को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सफलता सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

कच्छ क्षेत्रः विविध माल ढुलाई का प्रमुख केंद्र

गांधीधाम और कच्छ क्षेत्र से स्टील, सीमेंट, खनिज, कोयला, खाद, कृषि उपज, खाद्य तेल, औद्योगिक व खाद्य नमक, टीम्बर सहित विभिन्न वस्तुओं का बड़े पैमाने पर परिवहन होता है।

इन आवश्यकताओं को देखते हुए बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई:

▸▸ माल ढुलाई हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं यार्ड सुविधाओं का विस्तार

▸▸ लाइन क्षमता बढ़ाने तथा लोडिंग-अनलोडिंग की दक्षता में सुधार

▸▸ बढ़ती मांग के अनुरूप नए लॉजिस्टिक समाधान

▸▸ यात्रियों के लिए सुविधाओं के विस्तार के प्रस्ताव

▸▸ कच्छ में एयर कनेक्टिविटी सीमित होने के कारण रेल सेवा को मुख्य एवं सुरक्षित परिवहन साधन के रूप में और मजबूत बनाने की उम्मीदें

रेलवे–उद्योग साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता

श्री प्रकाश ने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि रेलवे उनके सुझावों को प्राथमिकता देकर भविष्य की योजना एवं सुविधाओं में शामिल करेगा। कच्छ क्षेत्र की तेजी से बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों को देखते हुए रेलवे अपनी क्षमताओं के विस्तार एवं आधुनिक लॉजिस्टिक्स समाधान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

पश्चिम रेलवे द्वारा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए गए हैं।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः

1.ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड – खातीपुरा (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09007 वलसाड – खातीपुरा स्पेशल के फेरों को 25 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09008 खातीपुरा – वलसाड स्पेशल के फेरों को 26 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

2.ट्रेन संख्या 09575/09576 राजकोट – महबूबनगर (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09575 राजकोट – महबूबनगर स्पेशल के फेरों को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09576 महबूबनगर – राजकोट स्पेशल के फेरों को 30 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

3.ट्रेन संख्या 09520/09519 ओखा – मदुरै (साप्ताहिक) स्पेशल

ट्रेन संख्या 09520 ओखा – मदुरै स्पेशल

के फेरों को 29 दिसंबर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09519 मदुरै – ओखा स्पेशल के फेरों को 02 जनवरी, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09007, 09575 एवं 09520 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 29 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास' की शुरुआत सामूहिक यात्रा से

▸▸ राज्य सरकार के चिंतन शिविर के लिए मंत्रिमंडल सहित उच्च अधिकारियों का दल अहमदाबाद से 'वंदे भारत' सुपर फास्ट ट्रेन में रवाना हुआ
▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में प्रशंसनीय प्रयोग

(जीएनएस)। गांधीनगर : वलसाड जिले के धरमपुर के निकट श्रीमद राजचंद्र आश्रम में आज यानी गुरुवार से शुरू हो रहे चिंतन शिविर के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और उच्च अधिकारियों का दल सवेरे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेन में सामूहिक रूप से रवाना हुआ। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य प्रशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाकर उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि करने के आशय से वर्ष 2003 से चिंतन शिविर की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता के साथ प्रशासनिक संवेदनशीलता को एक नई दिशा देने के लिए इस वर्ष 'सामूहिक चिंतन से सामूहिक विकास की ओर' की थीम के साथ चिंतन शिविर के 12वें संस्करण का आयोजन किया है। इस शिविर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य तथा मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों सहित हर कोई अपने सरकारी वाहन के बजाय भारतीय रेल सेवा की 'वंदे भारत' सुपर फास्ट ट्रेन में सहयात्री बनकर अहमदाबाद से रवाना हुआ।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गुजरात की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के संदर्भ में समीक्षा बैठक हुई

राज्य में राजमार्गों पर यातायात के 35 फीसदी से अधिक भार के मद्देनजर एनएचएआई द्वारा राजमार्गों की समुचित मरम्मत और आवश्यकता पड़ने पर विस्तारीकरण के कार्य जारी रहने चाहिए : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री ने अहमदाबाद-मुंबई, राजकोट-गोंडल-जेतपुर और अहमदाबाद-उदयपुर हाईवे के प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूरा करने के मुद्दे पर चर्चा की
▸▸ मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में एनएचएआई के हाईवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से 20 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आश्वासन दिया

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी :-

▸▸ सड़कों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश
▸▸ सड़कों के निर्माण और रिसर्फेसिंग में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें

(जीएनएस)। गांधीनगर, 27 नवंबर : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत संपन्न एवं प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई।

केंद्रीय मंत्री ने इस बैठक में अधिकारियों और ठेकेदारों से साफ-साफ कहा कि यह अत्यावश्यक है कि सड़कों की गुणवत्ता उच्च स्तर की हो तथा नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रिसर्फेसिंग के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि निर्धारित समयसीमा में सड़क निर्माण के सभी कार्य पूरे नहीं हुए और लापरवाही पाई गई, तो ठेकेदार को ब्लेकलिस्ट करने तक के कठोर कदम भी उठाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस बैठक की चर्चाओं के दौरान केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात का भार 35 फीसदी से अधिक रहता है, इस संदर्भ में एनएचएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन राजमार्गों की समुचित मरम्मत होती रहे और आवश्यकता पड़ने पर विस्तारीकरण के कार्य भी जारी रहें।

उन्होंने विशेष रूप से, अहमदाबाद-मुंबई, राजकोट-गोंडल-जेतपुर और अहमदाबाद-उदयपुर, तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूरा करने की दिशा में भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे गए मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए श्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की ओर से गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत हाईवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत करने का आश्वासन इस बैठक में दिया।

इस बैठक में एनएचएआई की ओर से गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत अब तक हुए कार्यों और आगामी समय में एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से शुरू की जाने वाली विभिन्न परियोजनाओं के बारे में भी प्रेजेंटेशन दिया गया। साथ ही, गुजरात में स्थित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा स्थिति, सड़कों के कार्य कब तक पूरे होने चाहिए थे और अभी जो कार्य बाकी रह गए हैं उन्हें कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इन सभी विषयों पर गहन चर्चा की गई। मुख्य सचिव श्री एम.के. दास ने गुजरात सरकार द्वारा हाईवे और सड़कों के प्रगतिरत कार्यों और केंद्र सरकार के साथ समन्वय की जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया और सलाहकार श्री एस.एस. राठौर, अपर मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ-साथ मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, सचिव डॉ. विक्रांत पांडे और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और गुजरात सरकार के सड़क विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग डिविजन सहित संबद्ध विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

भावनगर मंडल में हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में दिनांक 27.11.2025 (गुरूवार) को महान हिंदी साहित्यकार व पद्म भूषण से सम्मानित कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जन्म-जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मंडल में एक गरिमामयी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा जी द्वारा दीप प्रज्वलन तथा श्री बच्चन जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। संगोष्ठी में तीन कर्मचारियों तथा एक अधिकारी ने श्री बच्चन जी के जीवन वृत, साहित्यिक योगदान एवं प्रमुख रचनाओं पर अपनी सारगर्भित प्रस्तुति दी। साथ ही उनकी प्रसिद्द काव्य रचनाओं का वाचन कर उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम के दौरान श्री हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन और कृतित्व पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को स्थल पर ही पुरस्कार प्रदान किए गए। वक्ताओं को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक ने इस आयोजन की सराहना करते हुए साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से हिंदी भाषा के संवर्धन एवं साहित्यिक चेतना के प्रसार को प्रेरणादायी बताया।

कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अनुवादक श्री परेश बी. मजीठिया द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

इस अवसर पर अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी महोदय ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रसार को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रेरक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने का आग्रह किया।

दिनांक 27.11.2025 को मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भावनगर की तिमाही बैठक भी मंडल रेल प्रबंधक महोदय श्री दिनेश वर्मा जी की अध्यक्षता में तथा अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमांशु शर्मा जी की उपस्थिति में आयोजित की गई। इस बैठक में सभी शाखा अधिकारी, सभी सहायक मंडल इंजीनियर, तथा स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी अध्यक्षों ने भाग लिया। इस बैठक में पिछले तीन माह के दौरान सभी विभागों में किए गए हिंदी कार्य के समीक्षा की गई।

कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए राजभाषा विभाग की विशेष रूप से सराहना

रेलवे बोर्ड मुख्यालय में गरिमापूर्ण तरीके से मना 'संविधान दिवस'

'**(जीएनएस)**। संविधान दिवस' के अवसर पर बुधवार को रेल भवन स्थित रेलवे बोर्ड मुख्यालय में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सतीश कुमार ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की उद्देशिका का पाठ किया।

संविधान के प्रति दोहराया संकल्प

कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11:00 बजे बोर्ड के सम्मेलन कक्ष में किया गया। अध्यक्ष श्री सतीश कुमार की अगुवाई में उपस्थित सभी कार्मिकों ने भारत के संविधान की उद्देशिका (Preamble) का सामूहिक वाचन किया। इस दौरान सभी ने संविधान के मूलभूत आदर्शों का पालन करने और राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया।

डिजिटल भागीदारी पर भी जोर

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, इस भौतिक समारोह के अलावा डिजिटल माध्यमों से भी संविधान दिवस मनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को "MyGov.in" और "constitution75.com" वेबसाइटों के माध्यम से 'संवैधानिक लोकतंत्र' पर आयोजित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही, संविधान की उद्देशिका का ऑनलाइन वाचन कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का भी आह्वान किया गया।

क्यों मनाया जाता है यह दिवस?

गौरतलब है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया था। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है। रेलवे बोर्ड का यह आयोजन देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक नैतिकता के प्रति भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

तीन ट्रेनों का दिसंबर 2025 से वडोदरा मंडल के स्टेशनो पर अतिरिक्त ठहराव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए वडोदरा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर तीन ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. 10 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस–हरिद्वार एक्सप्रेस चांपानेर रोड और खरसालिया स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन का चांपानेर रोड स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 07:18 बजे/07:19 बजे तथा खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 07:48 बजे/07:49 बजे होगा। इसी तरह, 10 दिसंबर, 2025 को हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार– बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस खरसालिया और चांपानेर रोड स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 13:01 बजे/13:02 बजे तथा खरसालिया स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान 13:20 बजे/13:21 बजे होगा।

2. 01 दिसंबर, 2025 को अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19418 अहमदाबाद–बोरीवली एक्सप्रेस बाजवा स्टेशन पर रुकेगी। यह ट्रेन 02:27 बजे बाजवा स्टेशन पहुंचेगी और 02:29 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

देहरादून मेट्रो और ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में ठहराव, विकास के सपने हुए अधूरे

(जीएनएस)। देहरादून में वर्षों से योजना बन रही मेट्रो रेल परियोजना और ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर अब स्पष्ट ठहराव आ गया है, जिससे राज्य की राजधानी में आधुनिक परिवहन और प्रशासनिक सुविधाओं के विकास के सपने फिलहाल अधूरे नजर आ रहे हैं। देहरादून मेट्रो रेल परियोजना को केंद्र सरकार ने तकनीकी आधार पर अस्वीकार कर दिया है। पहले जनसंख्या मानकों के कारण यह प्रस्ताव खारिज हो चुका था, और अब उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत नियो मेट्रो योजना भी मंजूरी नहीं पा सकी। केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस योजना के अलावा अन्य विकल्पों पर काम करे, चाहे वह पीपीपी मोड (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) हो या राज्य अपनी वित्तीय क्षमता का उपयोग करके किसी अन्य परिवहन परियोजना को लागू करे। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने एलिवेटेड बस कॉरिडोर के विकल्प को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना की योजना बनाई जा रही है और जैसे ही वित्तीय मंजूरी मिलेगी, इसे कैबिनेट के सामने अंतिम स्वीकृति के लिए रखा जाएगा।

इसी बीच देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में नक्शे पास कराने का प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और दोबारा परीक्षण के लिए भेजा गया है। शहर में लंबे समय से चर्चा में रही ग्रीन बिल्डिंग परियोजना, जो हरिद्वार रोड स्थित पुराने रोडवेज वर्कशॉप में बनाई जा रही है, उसका काम भी बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इस ग्रीन बिल्डिंग का मकसद राज्य सरकार के 75 विभागों को एक ही परिसर में लाना और प्रशासनिक कार्यों को केंद्रीकृत करना है। हालांकि

परियोजना का कार्य 2019 में शुरू होना था और कैबिनेट ने नवंबर 2022 में आधिकारिक मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक परियोजना का केवल 35 प्रतिशत ही कार्य पूरा हुआ है। अगर काम इसी रफ्तार से चलता रहा तो अनुमान है कि यह परियोजना 2028 तक भी पूरी नहीं हो पाएगी। बजट की बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए प्रारंभिक बजट 150 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 206 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। देरी की प्रमुख वजहें प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अड़चन, परिवहन निगम से स्मार्ट सिटी को जमीन का हस्तांतरण, और तकनीकी चुनौतियां बताई जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मेट्रो और ग्रीन बिल्डिंग दोनों ही परियोजनाएं शहर की बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मेट्रो परियोजना के अस्वीकृत होने से शहर के नागरिक अब एलिवेटेड बस कॉरिडोर या अन्य विकल्पों पर निर्भर रहेंगे, जबकि ग्रीन बिल्डिंग की देरी प्रशासनिक कार्यों और सरकारी सेवाओं को केंद्रीकृत करने की प्रक्रिया को बाधित कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि परियोजनाओं की निरंतर निगरानी जारी रहेगी और केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद नई तकनीकी योजनाओं और संसाधनों के उपयोग से परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि, दोनों परियोजनाओं में ठहराव ने न केवल नागरिकों की उम्मीदों को झटका दिया है बल्कि शहर के विकास में गति को भी धीमा कर दिया है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि देहरादून के नागरिकों को मेट्रो सुविधा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा, जबकि ग्रीन बिल्डिंग के जरिए प्रशासनिक सुधार और विभागीय समन्वय का सपना भी अभी पूरा होने से बहुत दूर है।

यह मामला स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार के बीच समन्वय और कुशल योजना के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नागरिकों की सुविधा और शहर के विकास के लिए तय समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करना अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, और इस पर काम करने के लिए सभी पक्षों को तेजी से कदम उठाने होंगे।

घर से हिली भी नहीं कार, फिर भी कट गया टोल उपभोक्ता आयोग ने प्लाज़ा को 800 गुना जुर्माना ठोका, सिस्टम की लापरवाही पर बड़ा संदेश

(जीएनएस)। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने फास्टैग और टोल प्रबंधन की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के रहने वाले अशोक सैनी की कार उस दिन घर के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन उनके फोन पर अचानक एक मैसेज आया जिसमें बताया गया कि उनकी गाड़ी ने नेशनल हाईवे पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाज़ा को पार किया है और उनके फास्टैग से 55 रुपये की कटौती कर दी गई है। इस अजीबोगरीब स्थिति को उन्होंने पहले किसी तकनीकी समस्या समझा, लेकिन जब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कार उस समय घर से हिली भी नहीं थी, तो अशोक सैनी ने इसे टोल प्रबंधन की खुली लापरवाही मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाया।

आयोग में सुनवाई के दौरान अशोक सैनी ने अपने घर पर लगी सीसीटीवी फुटेज, वाहन की स्थिति से जुड़े दस्तावेज और फास्टैग कटौती का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। रिकॉर्ड से यह साफ प्रमाणित हो गया कि जिस समय टोल कटने का दावा किया गया, उस वक्त कार अपनी जगह पर ही पार्क थी और किसी भी टोल प्लाज़ा को पार करना तो दूर, सड़क पर भी नहीं उतरी थी। दूसरी तरफ टोल प्लाज़ा प्रबंधन अपने पक्ष में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं कर पाया। आयोग ने इसे सेवा में भारी कमी, उपभोक्ता अधिकारों का सीधा उल्लंघन और सिस्टम की गंभीर विफलता माना। आयोग ने कहा कि फास्टैग जैसी प्रणाली का उद्देश्य पारदर्शिता और सुविधा देना है, लेकिन गलत कटौती जैसे मामले न केवल उपभोक्ता को मानसिक व आर्थिक नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख को धूमिल करते हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए टोल प्लाज़ा प्रबंधक पर 55 रुपये की कटौती के मुकाबले करीब 800 गुना अधिक यानी 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही गलत तरीके से काटे गए 55 रुपये भी परिवाद दायर करने वाली तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया गया है। आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि उपभोक्ता से एकत्र किया गया पैसा छोटी राशि हो सकता है, लेकिन गलत कटौती का सिद्धांत बड़ा है, और किसी भी स्थिति में इस तरह की हरकत को नजरअंदाज़ नहीं किया जा सकता। आयोग ने यह भी टिप्पणी की कि इस तरह की घटनाएँ न केवल उपभोक्ता का भरोसा तोड़ती हैं, बल्कि हाईवे और टोल प्रबंधन की निगरानी प्रणाली की खामियों को भी उजागर करती हैं।

अशोक सैनी के लिए यह मामला सिर्फ 55 रुपये का नहीं था, बल्कि अपने अधिकारों की रक्षा का सवाल था, और उनका यह संघर्ष हजारों ऐसे उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बन गया है जो अक्सर इस तरह की गलतियों को तकनीकी गलती मानकर चुप हो जाते हैं। इस फैसले ने टोल प्रबंधन और फास्टैग सिस्टम को यह सख्त संदेश दिया है कि छोटी-सी गलती भी उपभोक्ता के साथ खिलवाड़ नहीं मानी जाएगी और ऐसी लापरवाही की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह फैसला उन सभी के लिए राहत देने वाला है, जिन्हें कभी-कभी फास्टैग कटौती को लेकर सवाल उठे हों या गलत मैसेज आए हों।

हाईवे किनारे से हटेंगे शराब के ठेके, राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को दी कड़ी नसीहत

(जीएनएस)। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीखी फटकार लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि नेशनल और स्टेट हाईवे को "लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर" में बदलने की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती। अदालत ने दो महीने की समय सीमा तय करते हुए प्रदेश भर में हाईवे से 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी शराब ठेकों को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट की इस सख्त टिप्पणी और फैसले ने राज्य सरकार के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें वह इन दुकानों को नगर सीमा के भीतर होने की बात कहकर बचाव कर रही थी।

इस याचिका पर सुनवाई चूरू निवासी कन्हैयालाल सोनी द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे किनारे शराब बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को राजस्थान सरकार नई परिभाषाएँ गढ़कर दरकिनार कर रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी और सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश की कुल 7665 शराब दुकानों में से 1102 दुकानें हाईवे के किनारे चल रही हैं। सरकार

ने यह भी बताया कि इन दुकानों से 2221 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलता है, लेकिन हाई कोर्ट ने इस दलील को सिरे से नकारते हुए कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा किसी भी राजस्व से अधिक महत्वपूर्ण है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नगर सीमा का बहाना बनाकर सरकार ने हाईवे को शराब बिक्री के सुरक्षित गलियारे की तरह इस्तेमाल होने दिया है, जिससे नशे में ड्राइविंग और गंभीर सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार की प्रवृत्ति न केवल सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशानिर्देशों के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा नागरिकों को प्रदत्त जीवन और सुरक्षा के अधिकार का भी सीधा उल्लंघन है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चाहे दुकानें शहर की सीमा में आती हों, लेकिन यदि वे हाईवे के किनारे स्थित हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से हटाना होगा। अदालत की इस टिप्पणी के बाद शासन प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया है। अब सरकार को यह तय समयसीमा के भीतर इन सभी 1102 ठेकों को हाईवे से हटाना होगा, चाहे इसके लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाने हों या लाइसेंस पुनर्संरचना करनी पड़े। फैसले के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य में दुर्घटनाओं पर नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास साबित हो सकता है, क्योंकि बीते वर्षों में नशे में वाहन चलाने से जुड़े हादसों में भारी वृद्धि देखी गई है।

राज्य के आबकारी विभाग के भीतर भी इस फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि शराब ठेके राज्य के राजस्व का बड़ा स्रोत रहे हैं। परंतु अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शासन व्यवस्था के लिए जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हाईवे पर शराब की उपलब्धता कई बार दुर्घटनाओं का कारण बनती है और सरकार द्वारा इसे नगर सीमा की तकनीकी परिभाषा के पीछे छिपाकर जारी रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता।

हाई कोर्ट की इस सख्ती के बाद अब राज्य सरकार को दो टूक शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि दिए गए समय के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी।

जयपुर में शिव मंदिर को 'अवैध कब्जे' का नोटिस, जेडीए की कार्रवाई से भड़का जनाक्रोश

(जीएनएस)। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में सड़क चौड़ीकरण योजना को लेकर एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने शहरभर में विरोध और नाराज़गी की लहर पैदा कर दी। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने गांधी पथ वेस्ट को 100 फीट तक विस्तारित करने की प्रक्रिया के तहत जिन 70 मकानों और दुकानों को नोटिस जारी किए, उन्हीं में एक पुराना शिव मंदिर भी शामिल कर दिया गया। जेडीए की प्रवर्तन टीम ने बाक़ायदा मंदिर की दीवार पर 'अवैध अतिक्रमण' का नोटिस चिपका दिया और सात दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा। नोटिस पर 'श्री शिव मंदिर' का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर स्थानीय लोग भड़क उठे कि आखिर इस नोटिस का जवाब देगा कौन—मंदिर का ट्रस्ट, पुजारी या स्वयं भगवान शिव?

मंदिर की दीवार पर चस्पा किए गए नोटिस में जेडीए प्रवर्तन शाखा के सीआई अरुण पूनिया के हस्ताक्षर हैं और हाईकोर्ट में दाखिल पिटीशन व सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। सर्वे के अनुसार मंदिर की बाउंड्रीवाल सड़क के दायरे में करीब 1.59 मीटर तक आती है, जिसे 'अवैध कब्जा' माना गया है। जेडीए की टीम का तर्क है कि सड़क को चौड़ा करने के लिए सभी निर्माण—चाहे निजी मकान हों या धार्मिक स्थल—सीमा में आने पर हटाए जाएंगे। लेकिन नोटिस के शब्द और तरीका लोगों को असंवेदनशील और जल्दबाज़ी भरा लगा।

मंदिर पर नोटिस लगते ही इलाके के निवासी मंदिर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सैकड़ों लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर जेडीए के खिलाफ जोरदार नारेबाज़ी की और चेतावनी दी कि यदि मंदिर को हटाने की कोशिश की गई तो वे बुलडोज़र के आगे लेट जाएंगे। लोगों का कहना था कि सड़क चौड़ीकरण जरूरी है, लेकिन मंदिर जैसे भावनात्मक स्थलों को इस तरह 'अतिक्रमण' बताकर नोटिस देना धार्मिक आस्था का अपमान है। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जेडीए ने बिना किसी बैठक, चर्चा या स्थानीय प्रतिनिधियों को जानकारी दिए सीधे मंदिर पर नोटिस चिपका दिया, जिससे पता चलता है कि कार्रवाई जल्दबाज़ी में की गई।

विरोध धीरे-धीरे संगठित होने लगा और बजरंग दल ने भी इस मामले में खुला मोर्चा संभाल लिया। संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों ने साफ कहा कि यदि सरकार समय रहते मामले को सुलझाए नहीं, तो वे पूरे राजस्थान बंद का आह्वान कर देंगे। बजरंग दल के राहुल शर्मा ने कहा कि अतीत में भी मंदिरों को हटाने वाली सरकारों को इसका राजनीतिक नुकसान भुगतना पड़ा है और यदि इस मामले में जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो गंभीर परिणाम होंगे।

स्थानीय लोगों की मांग है कि नोटिस जारी करने वाले प्रवर्तन अधिकारी अरुण पूनिया को तत्काल निलंबित किया जाए और मंदिर को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बाहर रखा जाए। कई नागरिकों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए वैकल्पिक समाधान खोजे जा सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों को लक्ष्य बनाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

फिलहाल जेडीए की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मामला लगातार राजनीतिक रंग पकड़ रहा है और शहर में माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द कोई स्पष्ट और संतुलित फैसला लेगा, जिससे न तो परियोजना रुकेगी और न ही धार्मिक भावनाएं आहत होंगी।

सुंदरता पर ताना, 12 लाख की मांग और तीन तलाक की धमकी मदरसे के मौलाना पर पत्नी की दहला देने वाली शिकायत

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सामाजिक संवेदनाओं, वैवाहिक उत्पीड़न और धार्मिक संस्थानों की छवि तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नौगांव के एक मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम देने वाले मौलाना सद्दाम हुसैन पर उसकी पत्नी गौसिया बानो ने जो आरोप लगाए हैं, वे किसी भी सामान्य घर की बेटी या बहन को कंपा देने के लिए काफी हैं। गौसिया बुधवार को अपने भाई के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और वहां जो कुछ कहा, उसका सार यह था कि शादी के बाद उसका जीवन धीरे-धीरे एक ऐसे अंधेरे कुएं में बदल गया जिसमें न सम्मान बचा, न सुरक्षा और न ही किसी रिश्ते की गर्माहट।

गौसिया बानो की शादी 25 अक्टूबर 2023 को टीकमगढ़ के ग्राम कुडीला में हुई थी। माता-पिता ने अपनी क्षमता से बढ़कर दहेज दिया था, पर शादी के चंद दिनों बाद ही पति और ससुराल वालों का व्यवहार इतना कठोर होता गया कि उसने खुद को एक ऐसी जगह कैद पाया जहाँ रोज़ गालियां, मारपीट और ताने उसका इंतजार करते थे। पीड़िता के अनुसार, पति सद्दाम हुसैन बार-बार उसे यह कहकर अपमानित करता था कि वह सुंदर नहीं है और इसी वजह से वह उसे तीन तलाक दे सकता है। लेकिन गौसिया के शब्दों में, "मेरी रंगत या चेहरा बहाना था असली वजह 12 लाख का दहेज था, जिसकी मांग पूरी न करने पर वह हर रोज़ मुझे तोड़ने की कोशिश करता रहा।"

गौसिया ने बताया कि सद्दाम ने उसे तीन अलग-अलग मौकों पर अपने पास बुलाया, पर हर बार वह या तो मारपीट का शिकार हुई या मानसिक प्रताड़ना का। आरोपों की फेहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। पीड़िता का कहना है कि सद्दाम का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है और इसी रिश्ते को खुला रास्ता देने के लिए वह उसे घर से हटाने की फिराक में था। इतना ही नहीं, गौसिया ने पुलिस के सामने बताया कि पति उसे पेट्रोल डाल कर जला देने की धमकी देता था। इस प्रताड़ना में अकेले पति ही नहीं, बल्कि ससुर गफूर अली, सास बफातिन, खालू खलील, खाला रुकसाना समेत कई रिश्तेदार शामिल थे, जो लगातार उसे मानसिक रूप से तोड़ते रहे।

गौसिया ने 13 अक्टूबर को नौगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दहेज उत्पीड़न, धमकी और उत्पीड़न का पूरा ब्यौरा था। पर शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में वह एसपी कार्यालय पहुंची और अपने सभी दस्तावेज पेश करते हुए न्याय की गुहार लगाई। उसने यह भी बताया कि आरोपियों ने उसका आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी अपने पास रख लिए और उसे घर से निकाल दिया।

पीड़िता के भाई ने भी एसपी के सामने कहा कि सद्दाम की नजर किसी और महिला पर है और इसी वजह से वह उनकी बहन को घर से हटाने की कोशिश कर रहा है। परिवार ने पहले टीकमगढ़ में भी रिपोर्ट दी थी, पर वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एसपी ने पूरे मामले को महिला थाना भेजकर जांच के आदेश दे दिए हैं।

गौसिया की आखिरी पंक्ति हर उस महिला का साहस बनकर उभरती है जो अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है—"अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मुझे सिर्फ न्याय चाहिए।"

जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर को

- संस्कृत के प्रचार-प्रसार और संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई 'योजना पंचकम्'
- राज्य के 34 स्थानों पर प्रतिभागी गीता के श्लोक और संस्कृति सुभाषितों का पारायण करेंगे, भगवद् गीता पर व्याख्यान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य में संस्कृत भाषा और साहित्य के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्राचीन भाषा संस्कृत को प्रोत्साहन देने और उसके संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड ने 'योजना पंचकम्' शुरू की है।

'योजना पंचकम्' में संस्कृत सप्ताह महोत्सव योजना, संस्कृत संवर्धन सहायता योजना, संस्कृत प्रोत्साहन योजना, श्रीमद् भगवद् गीता योजना और शत सुभाषित कंठपाठ योजना का समावेश किया गया है। इनमें से भगवद् गीता योजना और शत सुभाषित कंठ पाठ योजना के तहत प्रतिभागियों को जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

1 दिसंबर, 2025 को गीता जयंती के अवसर पर राज्य में जिला स्तर पर 34 स्थानों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से इन योजनाओं के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा, श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 12 और 15 का सामूहिक पारायण, लोगों के लिए संस्कृत प्रदर्शनी, भगवद् गीता पर व्याख्यान सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

आगामी समय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर संपूर्ण गीता कंठ पाठ योजना की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के दौरान श्रीमद् भगवद् गीता योजना और शत सुभाषित कंठ पाठ योजना में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के श्लोकों के उच्चारण और कंठ पाठ संबंधित श्लोकों के लय-छंद, उच्चारण की शुद्धता और कंठ पाठ की दक्षता के साथ ही भाव-भक्ति और आत्मविश्वास युक्त प्रस्तुति की समीक्षा की जाती है।

महाराष्ट्र में 'लंका' वाली लड़ाई : सत्ता के भीतर ही सत्ता का संग्राम गहराया

(जीएनएस)। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों उस दौर से गुजर रही है, जहां सत्ता सहयोगी दलों के बीच अविश्वास, आरोप और सार्वजनिक कटाक्ष ने माहौल को असामान्य रूप से तनावपूर्ण बना दिया है। महायुति सरकार की नींव भले ही भाजपा, शिंदे गुट शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के गठबंधन पर टिके होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि खींचतान अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां सहयोग से ज़्यादा संघर्ष दिखाई देने लगा है। डहाणू नगर परिषद चुनाव ने इस भीतरखाने चल रहे तनाव की परतें एक-एक कर पूरी तरह खोल दी हैं। पिछले सप्ताह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाजपा के उम्मीदवार को अहंकारी बताते हुए रामायण का सहारा लेकर टिप्पणी की कि जैसे अहंकार ने रावण की लंका जलाई, वैसे ही अहंकार यहां भी पतन की वजह बनेगा। इस टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को तिलियों की तरह भड़का दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब में कहा कि हमारा उम्मीदवार रावण नहीं, भरत है—राम का भाई—और अगर लंका जली तो उसे जलाने का अधिकार भरत को भी है। फडणवीस की यह टिप्पणी भले ही बिना नाम लिए की गई, लेकिन राजनीतिक जगत समझ गया कि यह पलटवार सीधे शिंदे पर ही तना हुआ तीर है। इसके बाद से यह स्पष्ट हो चुका है कि दोनों शीर्ष नेताओं के बीच ठंडी जंग अब गर्म हवा में बदल चुकी है। लेकिन यह विवाद यहीं नहीं रुका। नया मोर्चा तब बना जब शिवसेना के विधायक नीलेश राणे ने भाजपा के एक कार्यकर्ता के घर में घुसकर कथित स्टिंग ऑपरेशन किया और दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाताओं को पैसे बांटने की तैयारी हो रही थी। नकदी से भरे बैग मिलने का दावा होते ही भाजपा पाले में भूचाल आ गया। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने न केवल इस स्टिंग की पद्धति पर सवाल उठाए, बल्कि यह भी पूछा कि क्या किसी के घर में सीधे घुसना, यहां तक कि उसके शयनकक्ष तक जाना, किसी भी नैतिक या कानूनी मानदंड पर उचित ठहराया जा सकता है। उन्होंने यह अवश्य कहा कि यदि जांच में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वे कानूनी कार्रवाई का समर्थन करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी दोहराया कि स्टिंग के नाम पर की गई यह कार्रवाई अनुचित और अस्वीकार्य है।

हालांकि, दूसरे ही मोर्चे पर नीलेश राणे के खिलाफ उनके भाई और भाजपा नेता नितेश राणे खड़े हो गए। उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पास नकदी होना सामान्य बात है, क्योंकि कई लोग होटल, खनन, क्रशर और अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। उन्होंने आरोपों को 'अतिरंजित' बताते हुए यह कहकर खारिज किया कि मात्र नकदी मिलने से किसी को भी भाजपा को बदनाम करने का मौका नहीं लेना चाहिए।

उधर, इस पूरे विवाद को और पेचीदा बनाते हुए हिंगोली के भाजपा विधायक तानाजी मुटकुले ने दावा किया कि शिंदे गुट शिवसेना के विधायक संतोष बांगड़ ने 2022 में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने के एवज में 50 करोड़ रुपये लिए थे। मुटकुले ने कहा कि बांगड़ "बिना पैसे कोई काम नहीं करते" और राजनीतिक संकट की रात उन्होंने पलटी मारी, क्योंकि कथित सौदेबाजी पूरी हो गई थी। सहयोगी दल के विधायक पर इस तरह का आरोप महायुति की अंदरूनी खाई को और गहरा करता दिखाई दे रहा है।

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र में सत्ता साझा करने की यह व्यवस्था अब दरारों से भरे पुल की तरह हो चुकी है। एक ओर दहानू का चुनाव राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का प्रतीक बन गया है, दूसरी ओर विधायकों पर "खरीद-फरोख्त" के आरोप ने नैतिकता की बहस को गर्म कर दिया है। शिंदे और फडणवीस की टकराहट सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस भविष्य की ओर संकेत करती है जहां महायुति के भीतर अस्थिरता बढ़ सकती है।

इन सबके बीच जनता यह देखने को मजबूर है कि शासन, प्रशासन और विकास जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं और सत्ता का वास्तविक संघर्ष महज सीट, प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई में बदल चुका है। आने वाले हफ्तों में दहानू नगर परिषद चुनाव का परिणाम यह जरूर तय करेगा कि महाराष्ट्र में महायुति की संयुक्त राजनीति आगे किस दिशा में पहुंचेगी—एकता की ओर या टूट की राह पर।